

- प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, मुख्यमंत्री ने बलरामपुर और श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात।
- नीट यूजी मामले में अब अठारह जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में की जाएगी पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति।
- प्रदेश में कल से शुरू हुआ विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा ,आयोजित हुए विविध कार्यक्रम।

लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के बारह जिलों के 633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोण्डा में क्वानो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलिया, सिद्धार्थ नगर, शाहजहांपुर और कुशीनगर बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश में राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। केंद्रीय सूर्या कमांड ने बचाव कार्य में मदद के लिए शाहजहांपुर जिले में दो टुकड़ियां भेजी हैं। गर्गा और खन्नौत नदियों के बहाव में फंसे 264 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है।

लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। बाढ़ के कारण पलिया में तीन दिनों से फंसे लगभग 1000 नेपाली नागरिकों को पलिया बस यूनियनों की 14 बसों से सुरक्षित नेपाल राष्ट्र वापस भेज दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों के साथ कल शाहजहांपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण शाहजहांपुर शहर और उससे सटे हुए इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उधर, मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौषाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के लिये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तराई क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और दौरा किया। साथ ही बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें राहत राशि वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक राहत कार्य संचालित करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने और समय रहते सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जहां शरणालय बनाए गए हैं, वहां दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्रभावित परिवारों को हर 15 दिन में राहत सामग्री पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में 923 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ पीड़ितों को रखने के लिए एक हजार तैंतीस शरणालय बनाए गए हैं।

बाढ़ से भूमि प्रभावित है, जिसने 3 हजार 4 सौ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि इससे प्रभावित हुई है। यह एक एनडीआरएफ, एचडीआरएफ और पीएसी की यूनिट के साथ-साथ प्रशासन के स्तर पर भी नौकाओं की व्यवस्था की गई है। लंच पैकेट, खाद्यान पैकेट ये सब उपलब्ध कराई जा रही है। जनहानि पर दो परिवारों को हम लोगों ने यहा पर चेक वितरित किये। पशुहानि पर भी आपदा राहत कोष से पैसा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया।

शीर्ष अदालत में कल विवादास्पद नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं।

केंद्रीय कानून और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि एक जुलाई से लागू हुए तीनों नये कानून भारत के लोगों के जीवन को सरल बनायेंगे और त्वरित न्याय देने वाले साबित होंगे। कल वाराणसी दौरे पर आए श्री मेघवाल ने कहा कि नये कानून में पुराने कानून व्यवस्था की कमियों को दूर किया गया है। साथ ही त्वरित न्याय के लिए डिजिटल प्रक्रिया पर बल दिया गया है।(पीटीसी वाराणसी)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल-सीआईएसएफ में अब पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कल मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कांस्टेबल पद की भर्ती में 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु सीमा में छूट दी गई है।

उधर, आगरा में 14 जुलाई से एक अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। आगरा के सेना भर्ती कार्यालय के मुताबिक, आगरा कैंट के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रस्तावित सेना भर्ती रैली में वे युवा भाग लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2024 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम-सीईई पास कर लिया है।

रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। साल 2019 के लोक सभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिले के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। फ़ैसला सुनाए जाने के दौरान जया प्रदा कोर्ट में हाजिर रहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करती हैं और उन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया था।

उधर, सुल्तानपुर जिले में एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट में जमानत दे दी। उन्होंने कल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष न्यायधीश शुभम वर्मा ने उन्हें बीस बीस हजार रुपये के दो बेल बांड पर जमानत दे दी।

कल से पूरे प्रदेश में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत हो गयी। यह इकतीस जुलाई तक चलेगा। इस दौरान योग्य दंपति को परिवार नियोजन की महत्ता के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें उनकी मनपसंद सेवाएं भी दी जाएंगी। इस मौके पर कल बदायूं जिले में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता और जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जनजागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाया। मैनपुरी जिले में पूर्व मंत्री व विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण पखवाड़े के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले सारथी वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

गोरखपुर जिले में कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एके चौधरी ने जागरूकता वाहन को रवाना करने के बाद कहा कि समय के साथ परिवार नियोजन का दायरा विस्तृत हुआ है। इसकी शुरुआत शादी के पश्चात और प्रथम बार गर्भधारण के पहले ही हो जाती है। जिले के सभी ब्लॉक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मऊ और उन्नाव समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मौके पर रैलियों और गोष्ठियों के आयोजन किये गये।

प्रदेश में बीते चौबीस घंटे के दौरान हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी, जबकि सोलह लोग घायल हो गये। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हाथरस जिले में कलएक निजी बस और कंटेनर के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह सिकंदरा राऊ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर तेज रफ्तार बस के खड़े कंटेनर से टकराने से हुआ। हाथरस सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिये।

उधर, वाराणसी जिले में रोहनिया थानाक्षेत्र के खनाव गांव स्थित अखरी से अदलापुर जाने वाली सड़क पर बस और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में तीन किशोरों की मौत हो गयी।
